



हिमाचल में नई पोषण नीति की तैयारी तेज, देश का पहला व्यापक न्यूट्रिशन मॉडल बनने की ओर राज्य

हरियाणा में जहरीली हवा का खतरा बढ़ा, पीएम 2.5-पीएम 10 राष्ट्रीय सीमा से दोगुना

ट्राइसिटी में गैंगस्टर नेटवर्क का बढ़ता खतरा



शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नई और व्यापक पोषण नीति तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने संबंधित विभागों को 31 मई तक नई पोषण नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जहां सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखकर एक व्यापक न्यूट्रिशन पॉलिसी लागू की जाएगी।

सरकार के अनुसार इस नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, गर्भवती माताओं, बुजुर्गों और युवाओं में कुपोषण की समस्या को कम करना और संतुलित आहार को बढ़ावा देना है। नई नीति में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि और खाद्य आपूर्ति विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण पोषण संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।

हिमाचल में सरकारी नौकरियों के लिए "एंटी-चिट्टा टेस्ट" अनिवार्य



शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने घोषणा की है कि अब राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए "एंटी-चिट्टा टेस्ट" अनिवार्य किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और सरकारी सेवाओं में स्वच्छ एवं जिम्मेदार वातावरण सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में "चिट्टा" यानी सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सरकार ने इसे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती मानते हुए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नए नियम के तहत सरकारी नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के साथ सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।



चंडीगढ़, 11 मई 2026: हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। रेस्पायर लिविंग साईंसेज की ताजा रिपोर्ट ने राज्य की हवा को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से दोगुने से भी अधिक दर्ज किया गया है, जबकि अमोनिया गैस में भी 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि गतिविधियों और पशुधन से निकलने वाली अमोनिया अब जहरीले कण प्रदूषण की बड़ी वजह बनती जा रही है।

रिपोर्ट में 2024 से 2026 के बीच राज्य के 31 निगरानी केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि पीएम 2.5 का सालाना औसत 62.51 से 77.38 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच रहा, जबकि राष्ट्रीय मानक केवल 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वहीं पीएम 10 का स्तर 123.44 से 141.68 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जबकि इसकी सुरक्षित सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय है।

गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और मानेसर की दक्षिणी पट्टी सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल रही। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर-51, गुरुग्राम में अमोनिया का स्तर बेहद खतरनाक पाया गया। वर्ष 2025 में यहां अमोनिया का सालाना औसत 138.30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो निर्धारित सीमा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से काफी अधिक है। मार्च 2025 के दौरान लगातार तीन दिनों तक यहां 24 घंटे की सीमा 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर भी पार हो गई। इन दिनों अमोनिया का स्तर क्रमशः 409.21, 410.20 और 411.82 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया।

पशुधन वाले जिलों में भी अमोनिया का स्तर अधिक पाया गया। हिसार में राज्य की 9.2 प्रतिशत पशुधन

आबादी है, जबकि सिरसा, जींद, भिवानी और कैथल भी इस सूची में प्रमुख हैं। इन जिलों में कृषि और पशुधन गतिविधियों के कारण अमोनिया उत्सर्जन अधिक होने की आशंका जताई गई है। मुरथल, धारूहेड़ा और टेरी ग्राम जैसे इलाकों में भी अमोनिया की मात्रा चिंताजनक मिली।

रिपोर्ट में हरियाणा के लिए 10 सेंसर वाले विशेष अमोनिया निगरानी तंत्र की सिफारिश की गई है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरी क्षेत्रों के साथ हिसार, सिरसा और जींद जैसे पशुधन प्रधान जिलों में सेंसर लगाने का सुझाव दिया गया है। रेस्पायर लिविंग साईंसेज के संस्थापक रोनाक सुतारिया ने कहा कि अमोनिया अब केवल कृषि का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह पीएम 2.5 प्रदूषण का बड़ा कारण बन चुका है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अलग अमोनिया मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की मांग की।

ट्राइसिटी की राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड निपटारा, 40 हजार से अधिक मामलों का हुआ

चंडीगढ़: ट्राइसिटी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में आयोजित इस विशेष लोक अदालत के दौरान 40 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से सुलझाने के उद्देश्य से आयोजित इस पहल को आम लोगों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

चंडीगढ़ जिला अदालत सेक्टर-43 में इस दौरान कई विशेष बेंच स्थापित की गई थीं, जहां न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के सहयोग से मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, बिजली-पानी के बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, बीमा क्लेम, चेक बाउंस और सिविल मामलों सहित कई श्रेणियों के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।



अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत दिलाना है। कई ऐसे मामले जो वर्षों से अदालतों में लंबित थे, उन्हें आपसी समझौते और सहमति के आधार पर कुछ ही घंटों में सुलझा लिया गया। इससे न केवल लोगों का समय बचा बल्कि न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी मदद मिली।

लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने

मामलों के समाधान के लिए पहुंचे। कई परिवारों और पक्षकारों ने कहा कि सामान्य अदालतों की तुलना में लोक अदालत में समाधान अधिक आसान और तेज साबित हुआ। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसले अंतिम माने जाते हैं और इनके खिलाफ सामान्य रूप से अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवादों का स्थायी समाधान संभव हो पाता है।

न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें न्याय व्यवस्था को अधिक जनहितकारी और सुलभ बनाने का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं। ट्राइसिटी में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच इस तरह के आयोजन लंबित केसों को कम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

चंडीगढ़ जिला अदालत परिसर में पूरे दिन भारी भीड़ देखने को मिली। अलग-अलग विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और कानूनी सहायता टीमों भी मौके पर मौजूद रहीं ताकि लोगों को तुरंत सहायता मिल सके।



चंडीगढ़: ट्राइसिटी क्षेत्र में लगातार बढ़ती गैंगस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में पिछले कुछ महीनों के दौरान फायरिंग, रंगदारी और धमकी देने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

जानकारी के अनुसार ट्राइसिटी में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क अब केवल आपराधिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि कारोबारी वर्ग, बिल्डरों, क्लब संचालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को निशाना बनाकर रंगदारी मांगने के मामलों में भी तेजी आई है। कई मामलों में अपराधियों ने सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल कर धमकियां दीं, जिससे जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

हाल के महीनों में कुछ प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों के बाहर फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि कई वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी दूसरे राज्यों से जुड़े गैंगों के संपर्क में हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टर नेटवर्क का प्रभाव अब ट्राइसिटी तक पहुंचने लगा है।

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गैंगस्टर अब युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कई संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। साइबर सेल और इंटेलेजेंस विंग को भी विशेष रूप से सक्रिय किया गया है ताकि अपराधियों की गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।

चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। संयुक्त ऑपरेशन चलाकर संदिग्ध अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की जा रही है। कई इलाकों में रात के समय गश्त बढ़ाई गई है, जबकि होटल, गेस्ट हाउस और किराए के मकानों की जांच भी तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल निगरानी का सहारा लिया जा रहा है।

TruSoft

GST ACCOUNTING SOFTWARE WITH INVENTORY CONTROLS

ERP

Software that touches every part of your business.

SOFTWARE & WEB DEVELOPMENT
"Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works."



Software for Manufacturers, Traders, Dealers/Distributors

- ALSO FOR:
- Clinical Labs
 - Schools
 - Drycleaners
 - Transportation
 - Pharmaceuticals
 - Library
 - Non Banking/Finance
 - Weighing Scales
 - Institutes
 - Readymade Garments
 - Dairies
 - Cold Storage
 - Hotels, Restaurants
 - Apparels, Footwear
 - Shuttering
 - Sabzi Mandi

www.trusofterp.com

support@trusofterp.com

Smart Solutions. Stronger Businesses

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY